



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 585]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 29, 1983/पोष 8, 1905

No. 585]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 29, 1983/PAUSA 8, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 1983

का०आ० 936/18क/उ०वि०वि०अ०/83.— भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं०का०आ० 157(अ)/18क/उ०वि०वि०अ०/79, तारीख 27 मार्च, 1979 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) कलकत्ता स्थित मैसर्स लिली बिस्कुट कंपनी (प्राइवेट) लिमिटेड और मैसर्स लिली बारले मिल्स (प्राइवेट) लिमिटेड नामक औद्योगिक उपक्रमों का प्रवन्ध, 27 मार्च, 1979 से तीन वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण किया गया था, और पश्चिमी बंगाल सरकार के स्वर्ण और बन्द उद्योग विभाग जिसे अब औद्योगिक पुनर्निर्माण विभाग, के नाम से जाना जाता है, के सचिव को "प्राधिकृत नियंत्रक" के रूप में नियुक्त किया गया था ;

और, केन्द्रीय सरकार ने, अपनी यह राय होने पर कि लोक हित में यह समीचीन है कि उक्त आदेश का प्रभाव पूर्ववत् तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् जारी रहे, 31 दिसम्बर, 1983 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए ऐसे जारी रखने के लिए, समय-समय पर निर्देश जारी किए थे (देखिए भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० 178(अ)/18क/उ०वि०वि०अ०/82, तारीख 26 मार्च, 1982; का०आ० 688(अ)/18क/उ०वि०वि०अ०/82 तारीख 25 सितम्बर, 1982 और का०आ० 384(अ)/18क/उ०वि०वि०अ०/83, तारीख 31 मई, 1983);

और, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त आदेश 30 जून, 1984 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए प्रभावी बना रहे;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा

18क की उपधारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि तारीख 27 मार्च, 1979 का उक्त आदेश, 30 जून, 1984 तक तो जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अर्थात् के लिए प्रभावी बना रहेगा।

[फा०सं० 2(3)/80-मि०यु०सं०]

ए०पी० सरवान संगुवन मन्त्रि

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 29th December, 1983

S.O. 936|18A|IDRA|83.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 157(E)|18A|IDRA|79, dated the 27th March, 1979 (hereinafter referred to as the said Order), the management of the industrial undertakings known as Messrs Lily Biscuit Company (Private) Limited and Messrs Lily Barley Mills (Private) Limited, both located at Calcutta, had been taken over for a period of three years with effect from the 27th March, 1979 and the Secretary to the Government of West Bengal in the Department of Sick and Closed Industries, now known as Department of Industrial Reconstruction,

Calcutta, was appointed as "Authorised Controller";

And, whereas, the Central Government being of opinion that it is expedient in the public interest that the said Order should continue to have effect after the expiry of the period of three years afore-said, had issued directions from time to time, for such continuance for a further period upto and inclusive of the 31st December, 1983 [vide Orders of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 178(E)|18A|IDRA|82 dated the 26th March, 1982, S.O. 688(E)|18A|IDRA|82, dated the 25th September, 1982 and SO. 384(E)|18A|IDRA|83 dated the 31st May, 1983];

And, whereas, the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the said order should continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 30th June, 1984;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order dated the 27th March, 1979 shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 30th June, 1984.

[File No. 2(3)|80-CUS]
A. P. SARWAN, Jt. Secy.